राष्ट्रीय छात्रशक्ति

वर्ष ३३ अंक ५ अगस्त २०११ नयी दिल्ली मूल्य ५ रु. पृष्ठ ३६

'भ्रष्टाचार विरोधी देशव्यापी प्रदर्शन'

सड़कों पर उतरे लाखों छात्र

Credible Chhattisgarh
विश्वसनीय छत्तीसगढ़

स्त्रोत–केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन

सकल राज्य घरेलू उत्पाद–वृद्धि दर 11.49 प्रतिशत,*

विगत 5 वर्षों में औसत विकास दर 10.89 प्रतिशत
देश में सर्वाधिक तेजी से विकास करता राज्य

छत्तीसगढ़ में है भारत का–

- 20% आयरनओर
- 17% कोयला भण्डार
- 12% डोलोमाइट
- 12% वन
- 100% टिन

छत्तीसगढ़ में होता है भारत का–

- 16% खनिज उत्पादन
- 27% स्टील एवं स्पांज आयरन
- 30% एल्युमिनियम उत्पादन
- 15% सीमेंट उत्पादन

डॉ.रमन सिंह
मुख्यमंत्री

राष्ट्रीय छात्रशक्ति

शिक्षा क्षेत्र की प्रतिनिधि पत्रिका

सम्पादक
आशुतोष

सम्पादक मण्डल
अवनीश सिंह
संजीव कुमार सिन्हा

फोन : 011-43098248
ईमेल : chhatrashakti.abvp@gmail.com
ब्लॉग : chhatrashaktiabvp.blogspot.com
वेबसाइट : www.abvp.org

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के लिए राजकुमार शर्मा द्वारा बी-५०, विद्यार्थी सदन, क्रिश्चियन कॉलोनी, निकट पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट, दिल्ली-०७ से प्रकाशित एवं मॉडर्न प्रिन्टर्स, के. ३० नवीन शहादरा, दिल्ली- ३२ द्वारा मुद्रित।

संपादकीय कार्यालय :
"छात्रशक्ति भवन"
690, भूतल, गली नं. 21
फैज रोड, करोल बाग,
नई दिल्ली-110005

अनुक्रमणिका

विषय	पृ.सं.
संपादकीय	०४
भ्रष्टाचार के विरोध में सड़कों पर उतरे लाखों छात्र	०५
डूसू छात्रसंघः उपलब्धियां, कार्यक्रम और आंदोलन	१६
अक्षम्य है यह आपराधिक लापरवाही आशुतोष	२२
आखिर इस दहशत के पीछे मकसद क्या है? अवनीश सिंह	२४
मानसिक संकीर्णता के दायरे में सजी आजादी आकाश राय	२६
श्री अरविंद का शिक्षा दर्शन	२८
जेएनयू की बौद्धिक संस्कृति शंकर शरण	३०
व्यंग्य : इस देश का यारों क्या कहना... विजय कुमार	३३

वैधानिक सूचना: राष्ट्रीय छात्रशक्ति में प्रकाशित लेख एवं विचार तथा रचनाओं में व्यक्त दृष्टिकोण सम्बन्धित लेखकों के हैं। सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। समस्त प्रकार के विवादों का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा।

संपादकीय

२७ जुलाई २०११ दोपहर अंडमान और निकोबार के पोर्टब्लेयर में ३०० से अधिक छात्र-छात्राएं केन्द्र सरकार में हुई भ्रष्टाचार की घटनाओं पर अपना गुस्सा प्रदर्शन के माध्यम से जाहिर कर रहे थे। लेकिन यह घटना उस दिन देश के लगभग हर जिला मुख्यालय पर हो रही थी। भ्रष्टाचार को देश की प्रतिष्ठा और भविष्य के साथ खिलवाड़ मानने वाले यह छात्र अभावों से त्रस्त सामान्य जनता से जुड़कर अपना दायित्व निभाने हेतु रास्ते पर आए थे। विद्यार्थी परिषद् के आवाहन पर अपनी पढ़ाई को कुछ घंटे छोड़कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध लड़ने का संकल्प ले रहे थे। बंगलूर में २० हजार छात्र मानवश्रृंखला बना रहे थे तो दिल्ली के विश्वविद्यालय परिसर में भी प्रदर्शन हो रहा था।

भ्रष्टाचार के विरूद्ध छात्रों का यह रोष व्यर्थ नहीं जाएगा। इस चिंगारी को भ्रष्ट केन्द्र सरकार नहीं बुझा पाएगी। यह अवश्य ऐसी आग बनेगी, जो दुष्ट शक्ति का विनाश करेगी। छात्र यूं ही अपनी क्लास छोड़कर रास्ते पर नहीं आते, वे भी भ्रष्टाचार के विरूद्ध सरकार की मंशा एवं कुटिलता को समझ गये है। विद्यार्थी परिषद् के आवाहन पर आगामी ९ अगस्त से इस आंदोलन का नया दौर "भ्रष्टाचारियों सत्ता छोड़ो" प्रारंभ होगा तथा यह अगला कदम अधिक तीव्र व व्यापक होगा।

जेल में बंद भूतपूर्व संचार मंत्री ए. राजा ने अपने जवाब में कोर्ट में स्पष्ट रूप से दावा किया कि वितरण की सारी प्रकिया में प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री पूरी तरह सहभागी थे तथा उनकी सहमति से ही सारी प्रकिया हुई है। बहुत पहले उस तरह के पत्रव्यवहार उपलब्ध थे परंतु इस सरकार के प्रधानमंत्री एवं तत्कालीन गृहमंत्री पी. चिदंबरम इस पर झूठ बोलते आ रहे है। इसी तरह राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भी प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल एवं प्रमुख अधिकारियों की देख-रेख में सम्पन्न हुआ। उसके बावजूद करोड़ों रूपयों का घोटाला हो जाये तो स्वाभाविक ही प्रधानमंत्री को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। परंतु वह तो झूठ बोलना और जिम्मेदारी को टालना बड़ी ही बेशर्मी से कर रहे हैं।

राष्ट्रमंडल खेलों पर कैग की रिपोर्ट, २-जी मामले में मंत्री जेल में, सीवीसी मामले में स्वयं प्रधानमंत्री का झूठापन, कई परतें खुल रही है लेकिन केन्द्र सरकार में सब कुछ छुपाना, दबाना एवं विरोधियों को कुचलना चल रहा है। अभी तक २००४ से श्रीमती सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी के निजी विदेश दौरों की संसद को जानकारी नहीं है, जबकि वैसा करने की पद्धति है। देश की सर्वोच्च सत्ता में महत्वपूर्ण भूमिका निभानेवाले ऐसे क्यों? यह काफी गंभीर समस्या है।

सच पता करने के लिए इनको सत्ता से बेदखल होना जरूरी है, यह सभी को समझना होगा, अन्यथा यह तानाशाही हमारे देश को खोखला करेगी।

युवाओं को दो काम करने है। एक भ्रष्टाचारियों को सत्ता से बेदखल करना तथा भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्थाओं हेतु उनमें सुधार लाना। पहले काम हेतु व्यापक रूप में संघर्ष छेड़ना पड़ेगा तथा दूसरे काम हेतु हर व्यवस्था आधुनिक एवं हमारे देश के अनुकूल बनाने हेतु एक व्यापक बौद्धिक पहल करना।

स्वाभाविक परिसरों में बौद्धिक आंदोलन भी हो तथा रास्ते पर शक्ति भी दिखे। यह शक्ति एवं सृजन एक सुखद परिवर्तन लायेगी।

विद्यार्थी परिषद् ने आवाहन किया है कि ९ अगस्त से यह आंदोलन तेज हो, भ्रष्टाचारियों को घेरना प्रारंभ हो। सभी काम लगेंगे, हर विश्वविद्यालय के छात्र इसमें उतरेंगे, तो सरकार को झुकाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करते हुए भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्थाओं का सृजन होगा।

सुनील अंबेकर

'भ्रष्टाचार विरोधी देशव्यापी प्रदर्शन'

सड़कों पर उतरे लाखों छात्र

नयी दिल्ली। भ्रष्टाचार के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् द्वारा आयोजित देशव्यापी विरोध प्रदर्शन में देश की राजधानी नयी दिल्ली में भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम के अंतर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय के क्रांति चौक पर हजारों छात्रों ने रैली निकालकर जनसभा की।

छात्रों की सभा को संबोधित करते हुए अभाविप के राष्ट्रीय सह-संगठन मंत्री व यूथ अगेंस्ट करप्शन के राष्ट्रीय संयोजक श्री सुनील बंसल ने कहा कि हर स्तर पर पनप चुके भ्रष्टाचार से सामान्य जनता से लेकर हर कोई जूझ रहा है। वर्तमान केंद्र सरकार अपनी सारी नैतिक मर्यादा छोड़ कर पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार में लिप्त है। आये दिन हो रहे भ्रष्टाचार के नए खुलासों से यह साबित हो चुका है कि सरकार के कई मंत्री देश को लूटने का काम कर रहे हैं। स्वाधीनता से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी देश को लूटने का कार्य करती थी और आज यह काम सोनिया एंड कंपनी द्वारा किया जा रहा है। कांग्रेस का हाथ आम आदमी का साथ कब का छोड़कर भ्रष्टाचार के साथ हाथ मिला चुका है।

श्री बंसल ने कहा कि भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति ने देश के छात्र-युवाओं को आहत किया है, जिससे मजबूर होकर उन्होंने सड़कों पर उतरकर इसके विरुद्ध लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता जतायी है। अभाविप भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लडाई को तेज करके हुए सड़क पर उतर चुकी है और इसे निर्णायक मोड़ तक ले जाएगी। उन्होंने कहा कि इस आन्दोलन के माध्यम से अभाविप सरकार से मांग करती है कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कठोर कानून बनाये जाएँ जिसमें भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को कठोर सजा का प्रावधान हो। साथ ही देश की व्यवस्था में सुधार कर तंत्र को प्रभावी एवं मजबूत बनाया जाये।

उन्होंने कहा की यह आन्दोलन केंद्र सरकार को एक चेतावनी है, अगर आने वाले संसद सत्र में सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कारगर कदम नहीं उठाएगी तो इसका परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा।

इस्तीफा दें प्रधानमंत्री : उमेश दत्त

शिमला। भ्रष्टाचार के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् द्वारा आयोजित देशव्यापी विरोध प्रदर्शन में पूरे देश के अलग-अलग स्थानों पर लाखों युवाओं ने सड़कों पर उतरकर आज प्रदर्शन किया। इसी क्रम में अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री उमेश दत्त ने शिमला में भ्रष्टाचार के विरुद्ध आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर जनता में उपजे जन आक्रोश को देखते हुए सरकार को नैतिक रूप से इस्तीफा दे देना चाहिए।

भ्रष्टाचार के लिए प्रधानमंत्री को सीधे तौर पर जिम्मेदार बताते हुए श्री उमेश दत्त ने कहा कि इस खेल में श्रीमती सोनिया गाँधी एवं श्री राहुल गाँधी भी बराबर के दोषी हैं।

भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करने की बजाय सरकार शुरू से ही उनकी तरफदारी करती आ रही है। ए. राजा, सुरेश कलमाड़ी से लेकर थामश इसका उदाहरण है। दूसरी तरफ इस सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को प्रताड़ित एवं बदनाम करने का षडयंत्र रचा जा रहा है। जिसके लिए कांग्रेसनीत यूपीए सरकार सरकारी मशीनरी और सीबीआई का खुलकर दुरूपयोग कर रही है। अभाविप इसलिए ऐसे सरकार को अविश्वसनीय मानती है तथा भ्रष्टाचार समाप्त करने एवं भ्रष्ट लोगों को दण्डित करने में इसे अक्षम समझती है।

श्री दत्त ने बताया की भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी इस मुहिम को निर्णायक मोड़ देते हुए परिषद् के नेतृत्व में देश भर के विभिन्न महाविद्यालय परिसरों में ९ अगस्त के ऐतिहासिक दिन से भ्रष्टाचारियों गद्दी छोड़ो के नारे के साथ परिषद् अपनी आन्दोलान्नात्मक गतिविधियां और तीव्र करेगी। साथ ही स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर १५ अगस्त के दिन अभाविप देश भर में जगह-जगह तिरंगा यात्रा निकालकर भारत को भ्रष्टाचार से स्वाधीन करने का संकल्प लेगी।

अभाविप के नेतृत्व में आयोजित भ्रष्टाचार विरोधी इस मुहिम में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और पोर्टब्लेयर तक देश के सभी जिला केन्द्रों के लाखों छात्र भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते हुए सड़कों पर उतरे। देश भर के लगभग सभी प्रान्तों में हुए प्रदर्शनों में छात्रों की अच्छी सहभागिता रही, बेंगलुरु में 20,000 छात्रों ने अभाविप के नेतृत्व में मानव श्रृंखला बनायी। असम के गुवाहाटी में एक हजार से ज्यादा छात्र, सिलचर में तीन हजार छात्र, बिहार में विभिन्न केन्द्रों पर कुल 31470, झारखण्ड में 23 हजार, कर्नाटक में 30 जिलों में 140400 छात्र, राजस्थान में 52850, मध्य प्रदेश में 70,000, आन्ध्र प्रदेश में 62.500 उत्तरांचल में 29000 व उत्तर प्रदेश में 34000, छत्तीसगढ़ में 20,000, गुजरात 18,000 तथा हिमाचल में 13500 छात्र प्रदर्शन में सहभागी हुए। पोर्ट ब्लेयर में भी छात्र भ्रष्टाचार के विरोध में सड़कों पर आये। दिल्ली में दो हजार छात्रों ने नॉर्थ कैम्पस में रैली निकालकर जनसभा की। ऐसे ही देश के सभी हिस्सों से भारी प्रदर्शन हुए हैं।

प्रदर्शन का नेतृत्व शिमला में महामंत्री उमेश दत्त, ठाणे (महाराष्ट्र) में राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रो. मिलिंद मराठे, राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुनील आम्बेकर अहमदाबाद में, यूथ अगेंस्ट करप्शन के संयोजक सुनील बंसल दिल्ली, सह संयोजक विष्णुदत्त भोपाल में तथा एन. रविकुमार बेंगलुरु समेत आदि जगहों पर परिषद के प्रमुख नेताओं ने किया।

वाराणसी। भ्रष्टाचार व महंगाई के विरोध में बुधवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर धरना-प्रदर्शन किया। आक्रोशित छात्रों ने भ्रष्टाचार को मिटाने व काले धन की वापसी के लिए राष्ट्रपति से तत्काल बड़े नोटों के प्रचलन को बंद करने व विदेशों में जमा धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने की आवाज उठाई। परिषद ने चेताया कि १ अगस्त से शुरू हो रहे अधिवेशन में भ्रष्टाचार को समाप्त करने की दिशा में यदि सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो वे ९ अगस्त से 'भ्रष्टाचारियों सत्ता छोड़ो' आंदोलन शुरू करेंगे।

इस दौरान हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार घोटाले पर घोटाले कर रही है। भ्रष्टाचार में डूबी सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। छात्र नेताओं ने विदेशों में जमा धन को लाने के लिए फ्लोटिंग वारंट प्रक्रिया अपनाने, बड़े नोटों का प्रचलन बंद करने, सरकार की ओर से दी गई छूट धारक के खाते में सीधे पहुंचाने व ई-गवर्नेंस व्यवस्था शीघ्र लागू करने समेत

१३ सूत्रीय मांग पत्र राष्ट्रपति को प्रेषित किया।

सोनभद्र। सोनभद्र में अभाविप के प्रदेश संगठन मंत्री मुकेश त्यागी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिये हजारों की संख्या में युवा शक्ति ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। इस अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए श्री त्यागी ने कहा कि आजकल सारे देशवाशी केन्द्र में हुए घोटालों से उत्तेजित हैं। देश में भ्रष्टाचार के विरोध में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न माध्यमों से गुस्सा प्रकट हो रहा है।

प्रदेश सहमंत्री देवेन्द्र प्रताप ने कहा कि भ्रष्टाचार के तेज गति से बढ़ने का कारण अगर कानून का लचीलापन है तो नये कानून पर विचार करने की आवश्यकता है। आज सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है जो हर स्तर के भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा सकें।

गोरखपुर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरखपुर के कार्यकर्ताओं ने भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ जारी मुहिम के अंतर्गत शहर के विभिन्न मार्गों से जुलूस निकालते हुए पंत पार्क में जनसभा की और प्रदर्शन किया।

सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश मंत्री प्रवीण गुंजन ने कहा कि यह लड़ाई राजनीति या अपनी सुविधाओं को प्राप्त करने के लिये नहीं है, यह संघर्ष देश की प्रतिष्ठा और स्वाभिमान बचाने के

लिये है। वर्तमान समय में देश की सत्ता को संचालित करने वालों द्वारा किये जा रहे घोटालों से युवा हतास व निराश है। लेकिन इस भ्रष्टाचार रूपी अत्याचार से समाज मुक्ति दिलाने के लिये विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में युवा शक्ति सड़कों पर उतर चुकी है।

इलाहाबाद। भ्रष्टाचार दीमक की तरह इस देश को खोखला कर रहा है। यह बहुत ही अच्छा है कि इस पर सार्थक बहस की जा रही है। आज जनता देश की कमान अपने हाथ में लेना चाहती है। अन्ना और रामदेव को मिला समर्थन इसी जनाकांक्षा की अभिव्यक्ति है। यह बातें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र तिवारी ने कहीं। वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय यूनियन हॉल के सामने आयोजित परिषद के धरना-प्रदर्शन को संबोधित कर रहे थे।

सभा के पश्चात उपस्थित कार्यकर्ता जुलूस की शक्ल में विश्वविद्यालय चौराहा, मनमोहन पार्क, नेतराम चौराहा होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। बाद में भ्रष्टाचार के खिलाफ राष्ट्रपति को संबोधित एक १४ सूत्री ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा गया।

सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प

हल्द्वानी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर बुधवार को भ्रष्टाचार के खिलाफ यहां भी छात्रशक्ति सड़क पर उतर पड़ी। छात्रों ने जुलूस निकाला और धरना देकर केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प दोहराया। अभाविप के तमाम कार्यकर्ता एमबी महाविद्यालय में जुटे और वहां से जुलूस की शक्ल में नारेबाजी करते हुए विवेकानंद पार्क पहुंचे। यहां इन लोगों ने केंद्र सरकार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए धरना दिया।

इस दौरान विद्यार्थी परिषद के प्रदेश मंत्री ब्रजेश बनकोटी ने कहा कि केंद्र की कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार में नित नए आयाम स्थापित कर रही है। टू-जी स्पेक्ट्रम, आदर्श सोसाइटी घोटाला हो या फिर कामन वेल्थ गेम का घोटाला। इन सभी के तार सीधे तौर पर केंद्र सरकार से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार के कारनामों के चलते अब तो देश की जनता को भी शर्म आने लगी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ यह जंग अब रुकने वाली नहीं है, नौ अगस्त को विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में दो घंटे का चक्का जाम करेंगे।

छात्रा प्रमुख रीना रावत ने कहा कि धरने में मौजूद छात्र शक्ति से साफ हो गया है कि भ्रष्टाचार जैसे बड़े और अहम मामले को लेकर अब युवा शक्ति जागरुक हो रही है। इस शक्ति और जोश को बनाए रखने की जरूरत है। छात्रसंघ के पूर्व सचिव मनीष बलूनी ने कहा कि सभी राष्ट्रीय नेताओं की संपत्ति की जांच की जानी चाहिए और विदेशी बैंकों में जमा धन को सरकारी धन घोषित कर उसको भारत लाने का दबाव बनाना चाहिए।

विकासनगर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने भ्रष्टाचार के विरोध में राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत विकासनगर में रैली निकालकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने इस संबंध में एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भी भेजा।

अभाविप कार्यकर्ता 'मौन तोड़ो हल्ला बोलो' कार्यक्रम के तहत बुधवार को साढ़े ग्यारह बजे सिनेमा गली स्थित त्रिशला देवी जैन धर्मशाला में एकत्रित हुए और भ्रष्टाचार के विरोध में नारेबाजी करते हुए तहसील कार्यालय तक रैली निकाली। इस मौके पर अभाविप प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य गुरुप्रीत सिंह हैप्पी ने कहा कि विदेशों में जमा कालाधन वापस भारत लाया जाए और बड़े नोटों पर रोक लगाई जाए। विदेशों में जमा कालेधन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया जाना चाहिए। इस दौरान, दीपक कुमार, मोहित जैन आदि शामिल थे।

हरिद्वार। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने "मौन तोड़ो- हल्ला बोलो" अभियान के तहत जिलाधिकारी कैंप कार्यालय पर प्रदर्शन कर जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। इससे पहले परिषद कार्यकर्ताओं ने ऋषिकुल तिराहे से रैली निकाली। रैली देवुपरा चौक, बस स्टेशन होते हुए जिलाधिकारी कैंप कार्यालय पहुंची और वहां कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया।

परिषद कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर भ्रष्टाचार में लिप्त रहने का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार को नैतिकता के आधार पर तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए।

भ्रष्टाचार मुक्त हो भारत

पटना। भ्रष्टाचार के खिलाफ व कालाधन की वापसी की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बुधवार को सूबे के ३५ जिला मुख्यालयों पर रैली निकाल प्रदर्शन किया। पटना में अभाविप के सदस्यों ने पटना कालेज से रैली निकाली जो कारगिल चौक पर जाकर सभा में तब्दील हो गई।

हाथों में भगवा झंडा लिए अभाविप के सदस्य 'युवाओं का है सपना भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो अपना', 'मनमोहन सिंह इस्तीफा दो' का नारा लगा रहे थे। सदस्यों ने राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा।

इस मौके पर परिषद के क्षेत्रीय संगठन मंत्री गोपाल शर्मा ने कहा कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में प्रधानमंत्री विफल हैं। यह रैली केन्द्र सरकार को चेतावनी है कि अगर वह नहीं चेती तो परिणाम भुगतना पड़ेगा। विजय प्रताप ने केन्द्र सरकार को घोटालों की सरकार बताया। विवि मंत्री राहुल शर्मा ने आगामी ९ अगस्त से आंदोलन को तीव्र करने की घोषणा की।

मुजफ्फरपुर। भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की विशाल ''मौन तोड़ो, हल्ला बोलो'' रैली निकली। एलएस कॉलेज, कलमबाग चौक, तिलक मैदान रोड, सरैयागंज टावर होते हुए समाहरणालय पहुंची रैली में शामिल कार्यकर्ताओं ने लोगों को भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई का संदेश दिया।

बाद में विवि के ऑडिटोरियम में आयोजित सभा में जिला संयोजक केशरीनंदन शर्मा ने कहा कि भ्रष्ट नेताओं की करतूतों से आज देश शर्मसार है। सोनिया, राहुल व मनमोहन की तिकड़ी ने पूरे देश को बदनाम किया है। भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए युवाओं को ही आगे आना होगा। संभाग प्रमुख मुकुल शर्मा ने कहा कि देश के गरीबों के पैसे स्विस बैंक में जमा कर दलालों के माध्यम से घोटाले का सिलसिला अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

गया। केन्द्र सरकार के मंत्रियों द्वारा किये गये भ्रष्टाचार के कारण आज देश सदमे में है। नागरिकों के बीच भ्रष्टाचार के खिलाफ आक्रोश है। नित्य नये-नये घोटालों की परतें खुलने से भारत भ्रष्टाचार के क्षेत्र में ''सुपर पावर'' बन गया है। एक तरफ देश की ८० करोड़ जनता प्रतिदिन केवल २० रुपये पर जी रही है। वहीं दूसरी ओर ७० लाख करोड़ से अधिक रुपया विदेशों में कालाधन के रूप में भ्रष्टाचारियों ने जमा कर रखा है। प्रत्येक साल हजारों किसान की मौत गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी के कारण हो रही है। उपरोक्त दावा विद्यार्थी परिषद, गया के छात्र नेताओं ने बुधवार को समाहरणालय के समक्ष आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कही।

विद्यार्थी परिषद की ओर से गया कालेज एवं

जगजीवन कालेज से भ्रष्टाचार के खिलाफ रैली निकाली गयी। शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए रैली समाहरणालय के समक्ष सभा में तब्दील हो गयी। राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को परिषद के एक प्रतिनिधिमंडल ने सौंपा। ज्ञापन में १८ सूत्री मांग शामिल है।

जमशेदपुर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सैकड़ों सदस्यों ने भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए मौन तोड़ो, हल्ला बोलो के नारे के साथ प्रदर्शन किया। साथ ही उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। मांग की कि देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कराएं और हर हाल में विदेशों में जमा कालाधन वापस लाएं।

प्रदर्शन को संबोधित कर रहे नेताओं ने कहा कि पूरा देश भ्रष्टाचार के दलदल में फंसा हुआ है। यह आंदोलन भ्रष्टाचार के विरुद्ध देश की युवा व छात्र शक्ति को जागृत और संगठित करने की शुरुआत है। आगे यह लड़ाई और उग्र रूप लेगी। इस आंदोलन के माध्यम से विद्यार्थी परिषद ने राष्ट्रपति का ध्यान भ्रष्टाचार और काले धन की ओर आकृष्ट कराने का प्रयास किया है।

दुमका। भ्रष्टाचार के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 'मौन तोड़ो हल्ला बोलो' रैली निकालकर उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। इस दौरान यज्ञ मैदान से रैली निकाली गयी, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए उपायुक्त कार्यालय पहुंची। इस दौरान अभाविप कार्यकर्ताओं ने केन्द्र सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की।

इस अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कार्यक्रम समन्वयक जितेन्द्र सिंह ने भ्रष्टाचार में आंकठ डूबी केन्द्र सरकार को अविलंब बर्खास्त करने की मांग करते हुए कहा कि देश में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है। लेकिन इसे रोक पाने में केन्द्र सरकार पूरी तरह विफल साबित हो

कर दें। परिषद नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि केंद्र सरकार १ अगस्त से शुरू होने वाले संसद अधिवेशन में भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाती तो विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में ९ अगस्त से भ्रष्टाचारियों सत्ता छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा।

राष्ट्रीय संपत्ति घोषित हो कालाधन

जबलपुर। भ्रष्टाचार के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् ने रैली निकाली और आमसभा का आयोजन किया। बाद में राष्ट्रपति के

नाम ज्ञापन सौंपा। रैली डीएन जैन कॉलेज से शुरू कर सिविक सेंटर तक निकाली गई, जिसमें ३२८१ छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

इस संबंध में अभाविप के प्रदेश सहमंत्री उपेन्द्र धाकड़ ने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा व्याप्त भ्रष्टाचार जनमानस को यह सोचने पर मजबूर कर रहा है कि हम कैसे भ्रष्ट देश में जी रहे हैं। प्रांत कार्यकारिणी सदस्य एवं पूर्व राष्ट्रीय मंत्री सुश्री अश्विनी पराजंपे ने कहा कि अभाविप भ्रष्टाचार रोकने के लिए लाठी व गोली खाने के लिय भी तैयार है। केन्द्र सरकार को चेतावनी देते हुए कालाधन एवं घोटालों के पैसों को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने की मांग कार्यकर्ताओं ने की।

भ्रष्टाचार के विरोध में चार किमी लंबी रैली

जयपुर। राष्ट्रव्यापी आह्वान के तहत बुधवार को राजधानी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े छात्रों ने चार किलोमीटर लंबी रैली निकाल भ्रष्टाचार के खिलाफ हल्ला बोल अभियान प्रारंभ किया। रैली में करीब दो हजार छात्र-छात्राएं शामिल हुए। चार किलोमीटर लंबी रैली में छात्रों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई।

अल्बर्ट हॉल से महारानी कॉलेज, सुबोध कॉलेज होते हुए राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर पहुंची रैली सभा में तब्दील हो गई। सभा को छात्र नेताओं और संगठन पदाधिकारियों ने संबोधित करते हुए भ्रष्टाचार की लड़ाई अब छात्रशक्ति के स्तर पर लड़ने का आह्वान किया।

रैली को संबोधित करते हुए अभाविप के संगठन मंत्री विक्रांत खंडेलवाल ने कहा कि रामदेव और अन्ना हजारे के आंदोलन सरकार कुचल सकती है, लेकिन जिस दिन युवा तरुणाई भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी हो गई तो सत्ता का घमंड चूर होते देर नहीं लगेगी। उन्होंने छात्रशक्ति से आह्वान किया कि वे संगठन के ९ अगस्त से शुरू होने वाले भ्रष्टाचार के खिलाफ महाअभियान में शामिल होकर देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएं।

छात्रसंघ अध्यक्ष मनीष यादव ने कहा कि आज पूरे देश के १० लाख छात्र भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। अभी तो यह शुरूआत है, आगे लंबी लड़ाई बाकी है। राष्ट्रीय गीतों से रैली और सभा के दौरान माहौल देश भक्तिमय रहा।

जोधपुर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भ्रष्टाचार के विरोध में राष्ट्रव्यापी मौन तोड़ो आंदोलन का बुधवार को शंखनाद कर दिया।

परिषद के छात्रों ने नई सड़क चौराहे पर सभा आयोजित की और रैली निकाली। बाद में राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन एडीएम सिटी राजीव जैन को सौंपा।

अभाविप के कार्यकर्ता सुबह ११ बजे नई सड़क स्थित राजीव गांधी सर्किल पर एकत्रित होने लगे। करीब १ बजे भ्रष्टाचार के विरोध में छात्र सभा शुरू हुई।

उदयपुर। उदयपुर में टाउन हॉल में सभा करने के साथ ही रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में हजारों की संख्या में विद्यार्थी शामिल हुए। आंदोलन के लिए सुबह ११ बजे विद्यार्थी टाउन हॉल परिसर में जमा हुए। जहां आयोजित सभा को छात्र नेताओं ने संबोधित किया। वक्ताओं ने देश के बड़े घोटालों में वर्तमान केंद्र सरकार के मंत्रियों, नेताओं को दोषी करार दिया।

सभा के बाद टाउन हॉल से रवाना हुई विद्यार्थियों की रैली बापू बाजार, देहली गेट होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची। रैली में विद्यार्थियों ने बैनर, तख्तियां, पोस्टर के साथ ही भ्रष्टाचार के विरुद्ध नारे बुलंद किए। कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन के बाद छात्र नेताओं ने राष्ट्रपति व राज्यपाल के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा।

कठुआ। देश को भ्रष्टाचार मुक्त करवाने का सपना लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने देशव्यापी अभियान के तहत कठुआ में बुधवार को जागरूकता रैली निकाली। इस दौरान परिषद सदस्यों ने भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाने का संदेश दिया।

रामलीला मैदान से निकले परिषद सदस्य मुखर्जी चौक तथा शहीदी चौक से होते हुए शहीद भगत सिंह पार्क पंहुचे। इस दौरान देश को नई दिशा देने के लिए युवाओं का आह्वान किया गया। भगत सिंह चौक पर रैली सभा में तब्दील हुई। इस मौके पर अपने संबोधन में परिषद के राष्ट्रीय

कार्यकारिणी सदस्य रविंद्र ने कहा कि इस समय देश के युवा भ्रष्टाचार को दूर करने की मुहिम में खुल कर सामने आएं। वहीं, परिषद के नगर संयोजक राहुल देव ने कहा कि हम पथभ्रष्ट हुए नेताओं को उनके नैतिक कर्तव्य का बोध कराएं। इस अवसर पर कई अन्य परिषद सदस्यों के अलावा शहर के प्रमख गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की इस मुहिम का समर्थन किया।

'दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ'

उपलब्धियां, कार्यक्रम और आंदोलन

उपलब्धियाँ

पूर्वी कैंपस की मांग : डूसू अध्यक्ष जितेन्द्र चौधरी ने वि. वि. के कुलपति से मिलकर लंबे समय से चली आ रही पूर्वी कैंपस की मांग के बारे में बताया। कुलपति ने आश्वासन दिया कि अगले ३ साल की योजना में इसे पूरा कर लिया जाएगा। इमारत हेतु डिजाइन पास हो चुका है।

वाई-फाई : कैंपस में इग्जामिनेशन ब्रांच, आर्ट्स फैकल्टी, वीसी ऑफिस और मिरांडा हाउस कॉलेज में वाई-फाई की सुविधा दी गई।

डूसू ने सेमेस्टर सिस्टम के मुद्दे पर **'पहले कक्षा-फिर परीक्षा'** की मांग उठाई। इस मांग पर कार्रवाई करते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा की तारीखें एक महीने बढ़ा दीं जिससे कोर्स पूरा करवाने में मदद मिली और सेमेस्टर सिस्टम सहजता के साथ लागू किया जा सका।

सलाहकार समिति में छात्र प्रतिनिधि : पहली बार छात्र संघ अध्यक्ष जितेन्द्र चौधरी को दिल्ली विश्वविद्यालय सलाहकार समिति में शामिल किया गया।

जॉब फेयर : प्रशासन ने छात्र संघ की इस मांग को भी स्वीकार कर लिया कि हर साल परिसर में एक जॉब फेयर लगाया जाएगा।

स्टूडेंट सेल : छात्र-संघ से विभिन्न समुदाय के लोगों को जोड़ने के लिए पहली बार विभिन्न प्रकोष्ठों जैसे उत्तर-पूर्व, ऐंटी-रैगिंग, एंटी-स्मोकिंग, ओबीसी, एससी-एसटी सेल का गठन किया गया।

कार्यक्रम

प्रतिभा सम्मान समारोह : विश्वविद्यालय इतिहास में पहली बार शैक्षिक व अन्य क्षेत्रों में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले १२०० छात्रों को सम्मानित किया गया।

लोहड़ी उत्सव : देश के दूसरे हिस्सों की संस्कृति से अवगत कराने के लिए उत्तर-पूर्व के छात्रों के साथ लोहड़ी उत्सव मनाया गया।

रागिनी : पहली बार दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को साथ लाने के मकसद के साथ ग्रामीण गीतों और डांस का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया।

मार्शल आर्ट्स कैंप : छात्र-संघ प्रतिनिधियों ने छात्राओं की सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर १४ कॉलेजों में मार्शल आर्ट्स कैंप का आयोजन किया।

रेस अगेंस्ट करप्शन : भ्रष्टाचार के मुद्दे पर छात्रों का समर्थन और सहयोग लेने के लिए छात्र-संघ मैराथन-२०११ का आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न कालेजों और विद्यालयों के २५०० छात्रों ने हिस्सा लिया।

रक्तदान और स्वास्थ्य शिविर का आयोजन : शिविर में ३५० से अधिक छात्रों ने हिस्सा लिया।

'भ्रष्टाचार और न्यायपालिका की भूमिका' विषय पर सेमिनार का आयोजन।

डूसू के पूर्व-प्रतिनिधियों का मिलन समारोह : इसमें पूर्व-प्रतिनिधियों ने अपने अनुभव साझा किए।

प्रमुख आन्दोलन

राधिका तंवर हत्याकांड : डीयू के रामलाल आनंद कॉलेज की छात्रा राधिका तंवर की हत्या के बाद धरने और विरोध-प्रदर्शन आयोजित किए गए। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए हत्यारे को गिरफ्तार किया।

सुरक्षित और भयमुक्त कैंपस : कॉलेजों और उसके आसपास के इलाकों में छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हेल्प डेस्क बनाई गई। पुलिस सुरक्षा बढ़ाई गई और सीसीटीवी भी लगाई गई।

अरविंदो कॉलेज यौन-उत्पीड़न मामला : प्रो. नारंग के खिलाफ अरविंदो कॉलेज की गवर्निंग काउंसिल पर दबाव बनाया गया। छात्र संघ प्रतिनिधियों ने मांग की कि जब तक मामले का फैसला न आ जाए तब तक प्रो. नारंग को किसी भी प्रशासनिक कार्य में हिस्सा न लेने दिया जाए।

शिक्षा का व्यापारीकरण : डूसू प्रतिनिधियों ने शिक्षा का व्यापारीकरण रोकने के मुद्दे को लेकर कई कॉलेजों में पब्लिक मीटिंग और प्रदर्शन आयोजित किए।

भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान : केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रमंडल खेलों और २जी स्पेक्ट्रम मामले में किए गए भ्रष्टाचार के विरोध में विभिन्न कॉलेजों में धरने, प्रदर्शन आयोजित किए गए साथ ही जंतर-मंतर और राजघाट पर मौन जुलूस और धरना दिया गया।

a DUSU initiative
I m running

फाँसी दो, फाँसी दो

असम में भ्रष्टाचार के विरोध में प्रदर्शन

गोरखपुर वि.वि. गेट पर प्रदर्शनरत छात्र

केरल में भ्रष्टाचार के विरोध में प्रदर्शन

दिल्ली वि.वि. में प्रदर्शनरत अभाविप कार्यकर्ता

कुल्लू में विरोध–प्रदर्शनरत अभाविप कार्यकर्ता

मुम्बई में भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शन

पोर्ट ब्लेयर में भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन

साम्बा में भ्रष्टाचार के खिलाफ पदयात्रा

नागौर में धरने पर बैठे अभाविप कार्यकर्ता

भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शनरत छात्राएं

छात्र उठा है अब ललकार, नहीं सहेगा भ्रष्टाचार

RAJASTHAN GROUP OF INSTITUTIONS

ISO 9001-2008 Certified

Approved by AICTE, Ministry of HRD (Govt. of India) and Affiliated to Rajasthan Technical University

RAJASTHAN INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY

Co-Educational Institute in JAIPUR

Bhankrota, Ajmer Road, Jaipur.
Ph.: 0141-2251193, 9001099906,
9001099902, Fax: 0141-2251087
Email: rietjaipur@yahoo.com,
info@rietjaipur.com
www.rietjaipur.com

B.Tech.
- E & C ENGG.
- COMPUTER ENGG.
- INFO. TECH.
- E.E.E.
- MECH. ENGG.

M.Tech.
- DIGITAL COMM.
- COMPUTER SC. ENGG.
- POWER SYSTEM
- PRODUCTION ENGG.

•MBA •MCA

RAJASTHAN COLLEGE OF ENGINEERING FOR WOMEN

An Exclusive Girls Engg. College in JAIPUR

Bhankrota, Ajmer Road, Jaipur.
Ph.: 0141-2251276, 2251249,
9001099905, 09001895023,
Fax: 0141-2251249
Email: rcewjaipur@rediffmail.com
www.rcew.ac.in

B.Tech.
- E & C ENGG.
- COMPUTER ENGG.
- INFO. TECH.
- ELECTRICAL ENGG.

M.Tech.
- DIGITAL COMM.
- COMPUTER SC. ENGG.
- INFO. TECH.

•MBA •MCA

RAJASTHAN DENTAL COLLEGE & HOSPITAL

Co-Educational Institute in JAIPUR

N. H.-8, Bagru Khurd, Ajmer Road,
Near Toll Plaza Jaipur.
Ph. 91-141-2585457, 2585458,
9001999022 Fax : 91-141-2585458
Email: rajasthandental@yahoo.com,
www.rdchjaipur.com

B.D.S
M.D.S

B.Sc College of Nursing

- Approved by Dental Council of India
- Affiliated to University of Rajasthan
- Approved by Medical & Health Deptt. Govt. of Rajasthan
- Approved by Ministry of Health & Family Welfare, New Delhi

RAJASTHAN PHARMACY COLLEGE

Co-Educational Institute in JAIPUR

Bhankrota, Ajmer Road, Jaipur.
Ph. : 9001099901, 9610210826
Fax: 0141-2251249
www.rpcjaipur.com

B.Pharm
BACHELOR OF PHARMACY

- Approved by AICTE
- Affiliated to Rajasthan University of Health Sciences

RAJASTHAN INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY

Co-Educational Institute in CHITTORGARH

Village Aachora, Post Samelpura,
Chittor-Kota Highway, Chittorgarh.
Ph. 01472-235266, 9887295484,
9571933732
www.rietchittorgarh.com

B.Tech.
- E & C ENGG.
- COMPUTER ENGG.
- CIVIL ENGG.
- MECH. ENGG.
- E.E.

- Air-cooled Separate Hostel for Boys & Girls.
- Successful completion of Ten Years.
- Digital libraries and E-journals facility for all students.
- AC Conference Hall.
- Academic Alliance with Microsoft, Oracle, IBM.
- Architecturally designed beautiful building and fascinating landscape.
- Parallel Curriculum for Career Grooming and Personality Development.
- Tie-up with International Organizations like Hochschule-Bremen to provide students opportunities to work abroad.
- Runs no. of Master level programs in Engineering, Computer Applications and Management.
- Remarkable placements in MNC's and Government Organizations.
- Wi-Fi- Enabled Campus.
- Awarded with Rajasthan Energy Conservation Award 2010 by Govt. of Rajasthan.

राष्ट्रीय छात्रशक्ति की ओर से
सभी पाठकों को स्वतंत्रता दिवस की
हार्दिक शुभकामनाएं

स्वच्छ उदयपुर, स्वस्थ उदयपुर, सुन्दर उदयपुर

नगर परिषद उदयपुर (राज.)

अवैध निर्माण से बचें

- परिषद की स्वीकृति अनुसार बनाये अपना भवन
- बहुमंजिला ईमारतों में पार्किंग की समुचित व्यवस्था हो
- बहुमंजिला ईमारतों के पार्किंग स्थल पर किसी प्रकार का निर्माण न करें
- झीलों के इर्द–गिर्द निर्माण न करें और न ही झील परिधि क्षेत्र में निर्माण करें
- नगर परिषद की सम्पत्ति पर अतिक्रमण न करें और न करने दें। भवन के सेट बेक व पार्किंग स्थल को छोड़ते हुए निर्माण करें
- हेरीटेज लुक देते हुए अपने भवन का निर्माण करें
- प्रारूप के अनुसार नियमन के लिए आवेदन करें, राहत पाए।

प्रदूषण से मुक्ति का संकल्प

- ठोस कचरा निस्तारण के लिए शहर से दूर अत्याधुनिक प्रबंधन केंद्र
- परिषद के हरे भरे उद्यानों को साफ सुथरा करें

सूचना क्रांति की ओर बढ़ते कदम

- कम्प्यूटरीकृत आदर्श कार्य प्रणाली पर कार्य आरम्भ
- जन्म–मृत्यु पंजीयन का कम्प्यूटरीकरण
- वेबसाइट को अप–टू–डेट किया जाना
- जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए हेल्प लाईन सेंटर

मुख्य मेले

दशहरा–दीपावली मेला, हरियाली अमावस्या मेला, सुखिया सोमवार मेला

जनता से आग्रह

- शहर के विभिन्न चौराहे एवं मुख्य मार्गों पर अवैध होर्डिंग न लगाएं
- झीलों के अंदर एवं इर्द–गिर्द गंदगी न करें
- प्रतिबंधित पॅलिथिन का उपयोग न करें
- सड़क पर कचरा न फेंकें
- अपने पालतू पशुओं को सड़कों पर खुला न छोड़ें
- कचरा सड़क व नालियों में ना डालें, कन्टेनर में डालें
- जन्म–मृत्यु पंजीयन 21 दिवस में कराएं
- पालिका की समस्त देय का भुगतान समय पर करें
- विवाह पंजीयन अवश्य कराएं

परिषद का ध्येय

- त्वरित समस्याओं का निदान
- स्वच्छ, स्वस्थ एवं सुन्दर शहर रखने का संकल्प
- शहर के हेरीटेज लुक को बनाये रखना

महेंद्र सिंह शेखावत
उपसभापति

रजनी डांगी
सभापति

एवं समस्त पार्षदगण

अक्षम्य है यह आपराधिक लापरवाही

आशुतोष

अमेरिकी खुफिया एजेंसी एफबीआई द्वारा गुलाम नबी फई की गिरफ्तारी ने साबित कर दिया है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आई एस आई की पहुंच कितनी दूर और कितने गहरे तक हो गयी है। फई १९९० से अमेरिका में रह कर कश्मीर अमेरिकन कौंसिल चला रहा था जो कश्मीर की कथित आजादी के लिये वैश्विक जनमत जुटाने का काम कर रही थी।

कैलीफोर्निया के साथ ही ब्रुसेल्स और स्टॉकहोम जैसे यूरोपीय शहर उसकी गतिविधियों के केन्द्र थे। पाकिस्तान की गोष्ठियों में भी उसका आना-जाना लगा रहता था। मुजफ्फराबाद में कुछ समय पहले हुए एक सम्मेलन में फई के साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सैयद युसुफ रजा गिलानी भी मंच पर मौजूद थे।

इस घटना से यह भी साबित हुआ है कि दशकों पहले जो साजिश इस्लामाबाद में रची गयी थी उसकी शाखा-प्रशाखाएं अब अमेरिका और यूरोप सहित दुनियां के तमाम देशों में फैल गयी हैं। वहां के नीति निर्माताओं को प्रभावित कर कश्मीर की आजादी के पक्ष में लाने में फई सफल रहा है। इन देशों की बड़ी शख्सियतें फई की मेहमाननवाजी का लुत्फ लेती रहीं और बदले में भारत के खिलाफ चल रहे अभियान को बल देती रहीं। इसके लिये हर साल फई को ५ से ७ लाख डॉलर पाकिस्तान से प्राप्त होते रहे।

स्थिति की गंभीरता तब और बढ़ जाती है जब अनेक भारतीय बुद्धिजीवी भी इस षडयंत्र का हिस्सा बनते नजर आते हैं। फई की गिरफ्तारी के बाद कई नाम सामने आये हैं, जिन्हें उसने समय-समय पर भारत से बुलाया था। इनमें वरिष्ठ पत्रकार एवं गृह मंत्रालय की कश्मीर पर बने आधिकारिक वार्ताकार दल के अध्यक्ष दिलीप पडगांवकर, बहुचर्चित सच्चर समिति के अध्यक्ष अवकाश प्राप्त न्यायाधीश राजेन्द्र सच्चर, कश्मीर टाइम्स के संपादक वेद भसीन, हेडलाइन्स टुडे की संपादक हरिंदर बवेजा, मानवाधिकार के नाम पर आतंकियों के अधिकारों के पैरोकार गौतम नवलखा, कमल चिनॉय, प्रफुल्ल बिदवई, रीता मनचंदा, नक्सलियों के हमदर्द अग्निवेश, पाकिस्तान परस्त लेखक कुलदीप नैयर, बुकर पुरस्कार विजेता अरुन्धति राय, अंगना चटर्जी, संदीप पांडेय, अखिला रमन, मीरवाइज उमर फारुख एवं यासीन मलिक आदि शामिल हैं। इसी सूची में सुब्रह्मण्यम स्वामी का नाम आश्चर्यचकित करता है। यह सूची लगातार बढ़ती जा रही है। दुर्भाग्य से यह सभी लोग देश में न केवल बड़ी हैसियत रखते हैं बल्कि देश की नीतियों को प्रभावित करने की क्षमता भी रखते हैं।

फई की गिरफ्तारी के बाद इन सभी बुद्धिजीवियों ने अपने-आप को निर्दोष बताते हुए आई एस आई के साथ फई के रिश्ते उजागर होने पर आश्चर्य जताया है। कुलदीप नैयर ने कहा कि जिस सम्मेलन में वे गये थे उसमें पाकिस्तान के लोग भी थे तथा सबने स्वतंत्रतापूर्वक अपनी बात कही थी।

सुब्रह्मण्यम स्वामी ने कहा है कि वे भारतीय दूतावास की सलाह पर वहां गये थे तथा भारतीय दूतावास के एक कर्मचारी ने उनके भाषण के नोट्स भी बनाये थे।

सबसे फूहड़ तर्क पड़गांवकर ने दिया। उन्होंने कहा कि जब वे फई के निमंत्रण पर गये थे तब तक गुगल नहीं आया था जिससे वे फई की असलियत जान पाते। आश्चर्य यह है कि इन

सभी की मौजूदगी में फई द्वारा दिये गये भाषण और पारित किये गये कश्मीर की आजादी के प्रस्ताव से भी इन महापुरुषों के कान नहीं खड़े हुए।

भारतीय एजेंसियां दावा कर रही हैं कि उनके पास लम्बे समय से फई की भारत विरोधी गतिविधियों की जानकारी है। इसे सही माना जा सकता है क्योंकि उन्हीं के सूत्रों के आधार पर १९९४ में दिल्ली से प्रकाशित एक लोकप्रिय राष्ट्रीय समाचार पत्र में प्रकाशित लेख में फई की भारत विरोधी गतिविधियों की चर्चा की गयी थी। इसके बावजूद इन वरिष्ठ पत्रकारों और स्तंभकारों द्वारा यह कहा जाना कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी, हजम होने वाली बात नहीं है। साथ ही भारतीय एजेंसियों से भी यह सवाल किया जाना लाजिमी है कि उन्होंने इसे रोकने के लिये दो दशकों में क्या किया।

यहां यह भी उल्लेख किया जाना जरूरी है कि फई पाकिस्तान का नागरिक नहीं है। उसका जन्म श्रीनगर में हुआ और पढ़ाई अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में। यहीं उसके संबंध भारत विरोधी ताकतों के साथ बने। भारत में रहते हुए ही वह दुनियां भर में होने वाली भारत विरोधी गोष्ठियों में भाग लेता रहा। तब इन एजेंसियों के कान पर जूं क्यों नहीं रेंगी ? क्यों

किसी फोडे के नासूर बनने का इन्तजार किया जाता है ? क्यों समय रहते कार्रवाई नहीं की जाती ? किसके दवाब में भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के बाद भी ऐसे लोग कानून के फंदे में आने से बचे रहते हैं ?

सवाल उन शक्तियों की पहचान का भी है जो अलीगढ़ जैसे शहर में पढ़ने वाले फई जैसे विद्यार्थियों और आईएसआई के बीच संपर्कसूत्र का काम करती है। पहचान उस नेटवर्क की भी की जानी चाहिये जो एक साधारण नौजवान को अचानक अंतरराष्ट्रीय पहचान दिला देता है। समीक्षा उस सुरक्षा तंत्र की भी की जानी चाहिये जिसकी नींद एएमयू के एक साधारण विद्यार्थी द्वारा लगातार विदेश यात्रायें किये जाने पर भी नहीं टूटती। यह वह समय था जब विदेश यात्रा करने वालों पर आयकर विभाग भी निगरानी रखता था ।

जाहिर है कि जब तक पूरा नेटवर्क सक्रिय न हो, फई जैसे साधारण विद्यार्थी के लिये यह सब जुटा लेना संभव नहीं था। ९० के दशक के शुरुआती वर्षों में, जब देश सचमुच बारूद के ढ़ेर पर बैठा हुआ था, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ यह आपराधिक लापरवाही अक्षम्य है। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े तमाम सवालों का उत्तर यदि समय रहते नहीं ढूंढ़ा गया तो आने वाले समय में हमें और अधिक कठिन समय से गुजरना होगा यह निश्चित है।

आखिर इस दहशत के पीछे मकसद क्या है?

अवनीश सिंह

दिनांक १३ जुलाई २०११। हर रोज की तरह देश की आर्थिक राजधानी मुम्बई आज भी अपनी रफ्तार से दौड़ रही थी, तभी अचानक तेज धमाकों की आवाज होती है और उसके बाद चारों तरफ चीख पुकार। १० मिनट के अंतर पर झवेरी बाजार, दादर और ओपेरा हाउस में सिलसिलेवार तीन विस्फोट में कम से कम २३ लोगों की मौत और करीब १३६ से ज्यादा लोग घायल। इस तरह से एक और आतंकी घटना को अंजाम दे दिया जाता है।

धमाकों के बाद लोग सदमे में नजर आए, पर दुर्भाग्य की बात यह रही कि हर बार की तरह इस बार भी धमाकों का धुआँ छँटते ही केन्द्र सरकार और विपक्षी नेताओं ने एक-दूसरे पर दोषारोपण शुरू कर दिए। एक के बाद एक लगातार आतंकी हमलों को सहने वाली मुंबई आतंकियों का आसान निशाना बन चुकी है, लेकिन हैरान करने वाला तथ्य यह है कि आतंकी हमलों में हताहतों की संख्या के आधार पर यह शहर आतंक के केंद्र माने जाने वाले कराची और काबुल के साथ खड़ा है। धमाके की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से किसी आतंकी संगठन ने अभी तक नहीं ली है लेकिन शक की सुई इंडियन मुजाहिदीन (आईएम) और सिमी की तरफ साफ तौर पर इंगित करती है। आखिर इस धमाके के पीछे क्या है इनका मकसद..।

आतंकवादी संगठनों का बैक्टेरिया जिस दर से दुनिया में बढ़ रहा हैं उससे लगता है कि यह आने वाले सालों में लाइलाज बीमारी बन जाएगा। सिर्फ भारत की बात की जाए तो यहां विभिन्न राज्यों में १७५ से अधिक आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं। प्रमुख राजनीतिक व व्यवसायिक शहर इनके निशाने पर हैं। ये संगठन दिनोंदिन अपनी संख्या में बढ़ोत्तरी कर रहे हैं। पाकिस्तान, तालिबान, ईराक तथा अन्य पड़ोसी देशों में बच्चों को आतंकवाद की पढ़ाई में अव्वल बनाया जा रहा हैं। इनके हाथों में किताबों की जगह हथियार होते हैं। राजनैतिक समर्थन से पोषित हो रहे यह संगठन इतने हाइटेक हैं कि लैपटॉप से लेकर रोबोट रचने तक की कला इन्हें आती हैं।

इंडियन मुजाहिदीन (आईएम) यानि वो गुट जिसे केंद्र सरकार पिछले साल जून में आतंकी संगठन घोषित कर चुकी है। अलग-अलग धमाकों में ५०० से ज्यादा लोगों की जान लेने वाले इस आतंकी संगठन के तार पाकिस्तान से भी जुड़े हैं। इंडियन मुजाहिदीन को प्रतिबंधित सिमी और पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन लश्कर का मुखौटा माना जाता है। दिल्ली, मुंबई, यूपी और बैंगलोर के कई ब्लास्ट में इंडियन मुजाहिदीन का नाम शामिल रहा है। जेहाद के नाम पर बेगुनाहों का खून बहाने वाले इस आतंकी संगठन का नाम सबसे पहले २३ फरवरी २००५ को उस वक्त चर्चा में आया जब उसने वाराणसी में ब्लास्ट किया था। देश का प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन 'सिमी' (स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया) 'पापुलर फ्रंट ऑफ इंडिया' के नये बैनर तले अपने को संगठित कर रहा है। २००६ में भारत सरकार ने सिमी पर प्रतिबंध लगा दिया था, उसके बाद भी यह खुले आम अपनी गतिविधियां चला रहा है।

> "भारत सरकार के गृह मंत्री चिदम्बरम का कहना है कि इसे गुप्तचर संस्थाओं की असफलता नहीं माना जा सकता क्योंकि गुप्तचर संस्थाओं के पास इस प्रकार के धमाकों की कोई पूर्व सूचना नहीं थी। यदि इसकी व्याख्या की जाये तो इसका अर्थ तो यही हो सकता है कि आतंकवादियों को अपने षडयंत्रों की पूर्व सूचना चिदंम्बरम के विभाग को दे देनी चाहिए, उसके बाद वे उसकी रोकने की कोशिश करेंगे।"

वास्तव में किसी आपराधिक संगठन पर प्रतिबंध लगाना तब तक

निरर्थक होता है, जब तक कि उसके सारे सदस्यों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई न सुनिश्चित की जाए। केवल कानूनी प्रतिबंध लगा देने से तो पूरा संगठन निष्क्रिय नहीं हो जाता। पाकिस्तान में कितनी ही बार लश्कर-ए-तैयबा जैसे जिहादी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की कार्रवाई की गयी, लेकिन ये संगठन केवल अपना नाम व बैनर बदलते गये। भारत में भी यही हो रहा है। प्रतिबंध लगाकर सरकार भी निश्चित हो जाती है और प्रतिबंधित संगठन के सदस्य बिखरकर जगह-जगह अपने सुप्त संगठन बनाने में लग जाते हैं। पिछले कुछ सालों में इंडियन मुजाहिदीन सबसे ज्यादा तबाही मचाने वाला आतंकी संगठन बनकर उभरा है। सही यह होता कि बयानबाजी के बजाय इन घटनाओं को रोकने के लिए कोई रूपरेखा बनाई जाती। इस पर गंभीरता से चिंतन की जरूरत है, क्योंकि इन घटनाओं के होने के पीछे जो कारण हैं, वह इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि आतंकियों ने इस देश में किस हद तक जड़ें जमा ली हैं।

इसके साथ ही केन्द्र और राज्य सरकारों को भी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश की सुरक्षा के बारे में सोचना होगा। शीर्ष नेतृत्व को कुछ कठोर कदम उठाने ही होंगे, भले ही इसके लिए उन्हें अपने राजनैतिक हित भी खतरे में क्यों न डालने पड़ें, क्योंकि नेता हो या आम आदमी सबका वजूद इस देश से है, इसकी सुरक्षा सर्वोपरि है। दिल्ली, मुंबई या कोलकाता के वातानुकूलित क्लब और होटलों में गोष्ठी करने वाले कुछ भ्रष्ट बुद्धिवादियों के मन भले ही अपने इन साथियों के लिए धड़कते हों पर आम नागरिक के मन में इनके लिए कोई सहानुभूति नहीं है। उसकी दृष्टि में ये सब एक ही थैली के चट्टे-बट्टे हैं। गड़बड़ी कहाँ है और इसका "मूल" कहाँ है, यह सभी जानते हैं, लेकिन स्वीकार करने से कतराते, मुँह छिपाते हैं।

गत सन् २००८ में २६ नवम्बर को मुम्बई में आतंकी हमले हुये थे। तब आनन-फानन में आधुनिकीकरण के जरिये सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के लिए सरकार ने अनेक निर्णय लिये थे। पूर्व में लिये गये निर्णयों को दुहराया भी गया था। लेकिन इन तीन सालों में माकूल इंतजाम नहीं किये जा सके। इसी से हमारी सरकार की निष्क्रियता का बखूबी पता चल जाता है।

इसी प्रकार बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने का काम अभी तक पूरा नहीं हो सका। बांग्लादेश सीमा से लोग आसानी से भारत में प्रवेश कर रहे हैं। इसी प्रकार समुद्री सीमा पर निगरानी के लिये इन्टरसेप्टर वोट की व्यवस्था की जानी थी। लेकिन इन तमाम परियोजनाओं पर काम आगे नहीं बढ़ाया जा सका। यही हाल नक्सली क्षेत्रों का है। इन क्षेत्रों में जूझ रही सीआरपीएफ के पास अच्छी किस्म की बुलेटप्रूफ जैकेट नहीं है, बम निरोधक दस्ते नहीं हैं। इसका तो मतलब यही हुआ कि सरकार जमीनी योजनाये बनाने की अपेक्षा हवा-हवाई उपायों में ही फंसकर रह गयी है। जबकि जरूरत इस बात की है कि देश की आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा की बिल्कुल भी अनदेखी न हो वरन् देश के दुश्मनों से कड़ाई से निपटा जाये।

> "'देशप्रेमियों के लिए जेल और आतंकवादियों के लिए बेल' की नीति के चलते पूरे देश में आतंकवाद की आग फैल गई है। पिछले सात वर्षों में मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, बैंगलुरु और पुणे जैसे शहर भी बार-बार निशाना बनने लगे। दिग्विजय सिंह के पद चिन्हों पर राहुल गांधी भी चल पड़े हैं। राहुल देश की तुलना अफगानिस्तान, ईरान और ईराक से कर रहे हैं, तो गृहमंत्री पी. चिदंबरम् मुंबई के निवासियों से यह शुक्र मनाने को कह रहे है कि एक के बाद दूसरा हमला होने में 'पूरे ३१ माह का' समय लगा।"

मानसिक संकीर्णता के दायरे में सजी आजादी

आकाश राय

आजादी, जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने लम्बे समय तक राष्ट्रविरोधी शक्तियों से संघर्ष किया और अपने प्राणों की आहुति देकर हमें स्वतंत्र वातावरण में सांस लेने का हक दिलाया। आज इस आजादी को हमने अपने निजी स्वार्थ और एकमेव लाभ की मनोदशा के आधार पर फिर से किसी और के यहां गिरवी रख दिया है। कल तक जिस आजादी के सुनहरे स्वप्न को अपनी पलकों में संजोकर हमारे देश के स्वातंत्र वीरों ने अपनी भारत माता को विदेशी ताकतों से आजाद कराने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, आज उसी भारत में सियासत और तुष्टीकरण की ऐसी आंधी बह चली है की आजाद देश की गुलाम जनता सत्तासीन निरीह हुकूमत के खिलाफ जूझने पर मजबूर है।

लूट आज भी बदस्तूर जारी है, फर्क सिर्फ इतना है कि उस समय गोरे अंग्रेजों ने देश को दीमक की तरह खोखला किया और आज काले अंग्रेज इस काम को कर रहे हैं। खेल वही है बदले हैं तो सिर्फ इसके किरदार। उस दौर में सत्ता और धन पर नियंत्रण अँगरेज हुक्मरान और देसी रजवाड़ों और नवाबों तक सीमित था आज सफेद पोश नेताओं, अफसरों और सत्ता के दलालों के हाथ में है।

आजादी के बाद बने पहले प्रधानमंत्री द्वारा सन् १९५१ में पंचवर्षीय योजनाओं का शुभारंभ किया गया था जिसके अंतर्गत देश का विकास किया जाना था। लेकिन आज कितने लोग हैं जो जानना चाहते है कि पंचवर्षीय योजना के तहत क्या कार्य किये गये हैं? प्रत्येक वर्ष कितना पैसा पंचवर्षीय योजनाओं के नाम पर खर्चा जाता है यह जानने वाला कोई नहीं?

स्वतंत्रता पूर्व जिस अवस्था में भारत और भारतवासी थे, उसमें देशवासियों पर केवल सरकार के खिलाफ कार्य न करने देने की पाबंदी थी। लेकिन आज स्थिति उससे भी अधिक भयावह हो गयी है। एक तरफ महात्मा गाँधी के रामराज्य की परिकल्पना को साकार करने का स्वप्न दिखाकर देश के हुक्मरान देशवासियों के खून-पसीने की कमाई को विदेशी बैंको में जमा कर रहे हैं तो दूसरी तरफ मंहगाई की चाबुक निरीह जनता की कमर तोड़ रही है। बाकी बची कसर सरकार का 'कर तमाचा' आये दिन हमारे शक्ल की मालिश कर पूरा कर रहा है। क्या इसी आजादी की संकल्पना हमारे देश के अमर शहीदों और महापुरुषों ने की थी...? वास्तव में हमें आजादी नहीं मिली है, बल्कि देश की सत्ता को विदेशी गोरों से स्थानांतरित कर उन्हीं की नुमाइंदगी करने वाले देशी काले लोगों के हाथों में सौंप दिया गया है। आज भी हम मानसिक रूप से गुलाम हैं।

सांस्कृतिक दृष्टि से भारत एक पुरातन देश है, किंतु राजनीतिक दृष्टि से एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में भारत का विकास होना चाहिए था जिसमें स्वतंत्रता-संग्राम के साहचर्य और राष्ट्रीय स्वाभिमान के नवोन्मेष के सोपान का दर्शन हो। लेकिन अब समय की आवश्यकता है कि सभी राजनीतिक पार्टियां और नीति निर्देशक तत्व देश की जनता के सामने यह स्पष्ट करें कि वे देश को

किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। स्पष्ट करें अपनी-अपनी रणनीति की देश से गरीबी हटाने,भ्रष्टाचार को मिटाने, आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने, नक्सलवाद के सफाए, समस्त भारतीयों को निर्भय एवं सुखी, संपन्न और विश्व में भारत को एक भरोसेलायक आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए क्या पुष्ट योजनाएं हैं और किसके पास हैं? देश को विकास पथ पर ले जाने की बात करने वाले हमारे राजनेता धनलिप्सा को जागृत किये हुए हैं और जनता को विश्वास का घोल पिलाये जा रहे है कि सरकार उन्हीं के लिए तो प्रतिबद्ध है।

देश की जनता और आजादी के परवानों ने अनगिनत कुर्बानियां दे कर देश को अंग्रेजों से आजाद करवाया ताकि इस देश की धन संपदा इस देश की गरीब जनता को नसीब हो और वे अपना भविष्य संवार सकें। लेकिन आज देश में भ्रष्टाचार चरम पर है। घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं। नेता भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हैं। ऐसे में यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि विदेशी गोरे लोगों के पिटठू, जो सरकार बन हमारे देश की दिशा और दशा तय कर रहे हैं, इन्हें देश और देश के विकास में कोई रूचि नहीं है।

आजाद भारत की व्यवस्था और सामाजिक स्थिति पर कई सवाल खडे होते हैं, जिनमें मुख्य यह है कि 'ऐसी आजादी किस काम की जो हमें मानसिक गुलामी और संकीर्णता के दायरे से मुक्त ना कर सके?श

आजादी शब्द जिसका मतलब ही है कि इंसान को अपने मन के मुताबिक कार्य करने की स्वतंत्रता हो। पर वास्तविकता यह है कि हमारी आजादी अन्य लोगों की सोच पर निर्भर करती है कि वह इसके बारे में क्या सोचते हैं। ऐसे में स्पष्ट है कि आज आजादी की आबो-हवा में सांस लेने वाले लोग अपनी मौलिक सोच को अब भी सामने वाले की बातों का गुलाम बना कर रखे हुए हैं।

शाब्दिक अर्थो में लोग आजादी को केवल अपने लाभ और स्वार्थसिद्धि का माध्यम मानते हैं। किसी को इस बात से कोई फर्क नहीं पडता कि आजादी का मूलभाव क्या है और किस लिए लाखों देशवासियों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। सरकारी अधिकारी अपने दस से पांच की कार्यावधि में चाय और पान के साथ बातों के हवाई किले बनाते हुए समय को बिताते हैं और वेतन का भोग लगाते हैं। ऐसे में कैसे कहा जाय की इसी आजादी के लिए कभी देश में संग्राम हुआ था।

भारत ऐसा देश है जिसके पास दुनिया का लिखित संविधान है। परन्तु अब भारत जिसने हर संकट की घड़ी में बिना धैर्य खोये हर मुसीबत का सामना किया, अनेकों बुराइयों से जकड गया मसलन आतंकवाद, भ्रष्टाचार, आर्थिक विषमता, जातिवाद, सत्ता लोलुपता के लिए सस्ती राजनीति करना जो कि कभी कभी सामाजिक वैमनस्य के साथ साथ देश की एकता को ही संकट में डाल देता है, राजनीति में वंशवाद व भाई-भतीजावाद, न्यायिक प्रक्रिया में विलम्ब आदि-आदि। आज तो आम आदमी कहने लगा है कि ऐसी आजादी किस काम की। जिसने नौकरशाही के भ्रष्टाचार और चालबाजियों ने लोगों के दैनिक जीवन में निराशा घोल दी हो। जहाँ कुशासन ने न्याय-तंत्र की निष्पक्षता में लोगों की आस्था हिला दी हो।

स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अवसर पर स्कूलों, कालेजों और अन्य सरकारी भवनों पर तिरंगे झंडे को फहराने भर से आजादी का औचित्य सामने नहीं आ पाता। जिस उद्देश्य से भारत देश की आजादी के लिए लोगों ने प्रयास किये कि देश में समानता, सम्पन्नता और विकास की छटा लहराया करेगी, सब ओर खुशहाली होगी और सब एकजुट होकर रहेंगे।

यह सारी उद्देश्यपरक वैचारिकता आज कहीं विलुप्त हो चुकी है। कष्टों से मिली आजादी पर हर भारतीय की अपनी-अपनी अलग राय है। कोई देश में कानून व्यवस्था, राजनीतिज्ञों एवं सरकारी अफसरों की बेईमानी का रोना रोता है। तो कुछ लोग अपनी स्वार्थता को ही आजादी का परिचायक बताते हैं। लेकिन इससे अलग एक और भारतीय वर्ग है जो सरकार और सरकारी कार्यगुजारियों की मार झेल रहा है। उनके लिए आजादी के मायने अलग हैं जब आपको इंसाफ के लिए लडाई लडनी पडे तो इसका मतलब है कि आपको सही मायनों में आजादी नहीं मिली है।

भारतीयता के व्याख्याता महर्षि अरविंद

योगीराज श्री अरविंद आधुनिक भारत के उन थोड़े- से प्रमुख शिक्षा- दार्शनिकों में से है, जो पौर्वात्य और पाश्चात्य संस्कृतियों के समन्वय की कड़ी हैं। प्रत्येक दार्शनिक के शिक्षा संबंधी विचार उसके दार्शनिक विचारों पर ही आधारित होते हैं।

श्री अरविंद के मतानुसार बालक की शिक्षा उसकी प्रकृति में जो कुछ सर्वोत्तम, सर्वाधिक शक्तिशाली, सर्वाधिक अंतरंग और जीवनपूर्ण है, उसे अभिव्यक्त करना होनी चाहिए। मनुष्य किया और विकास के जिस सांचे में ढलना चाहिए। वह उसके अंतरंग गुण और शक्ति का सांचा है। उसे नयी वस्तुएं प्राप्त करनी चाहिए, परंतु वे उन्हें सर्वोत्तम रूप से और सबसे अधिक प्राणमय रूप में स्वयं अपने विकास, प्रकार और अंतरंग शक्ति के आधार पर ही प्राप्त हों।

इस प्रकार शिक्षा का उद्देश्य आत्मशिक्षा है। वह एक प्रयोजनमय प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति अपनी अंतरंग प्रकृति और उसकी अभीप्साओं को प्राप्त करता है। इस प्रक्रिया में शिक्षार्थी, शिक्षालयों और पुस्तकों का उपयोग करता है। शिक्षक शिक्षार्थी को एक ऐसे मार्ग पर ले जाता है। जहां शिक्षार्थी को अपनी आंतरिक प्रकृति ही उसका पथ प्रदर्शन करती है।

श्री अरविंद टुकड़ों में बांटकर शिक्षा देने के विरुद्ध हैं। शिक्षा समन्वित होनी चाहिए। शिक्षार्थी के मस्तिष्क पर कभी भी इतने अधिक विषयों का बोझ नहीं लादा जाना चाहिए कि यह किसी का भी अध्ययन भली प्रकार से न कर सकें। पांच-छः विषय पढ़ाने की अपेक्षा दो - तीन विषयों पर अधिकार कराने का प्रयास अधिक उत्तम है। बालक की शिक्षा सात या आठ वर्ष की आयु में आरंभ की जा सकती है : क्योंकि इस आयु में वह पर्याप्त समय तक किसी विषय पर ध्यान केन्द्रित कर सकता है। इससे कम आयु में शिशु के लिए किसी विषय पर अधिक समय तक ध्यान जमाना संभव नहीं है। इससे पूर्व उसे उसके चारों ओर के परिवेश से परिचित कराया जा सकता है।

आज भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विचार को और शिक्षकों के सामने जब अनेक समस्याएं भयंकर रूप से उपस्थित है, इन समस्याओं के मूल कारणों को खोजने में श्री अरविंद के शिक्षा - दर्शन से सहायता ली जा सकती है : क्योंकि अन्य क्षेत्रों के समान शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने व्यापकता और गहराई- दोनों की दृष्टि से सत्य की खोज की है। इसीलिये उनका शिक्षा - दर्शन केवल समकालीन भारतीय शिक्षा - दर्शन में ही नहीं, अपितु विश्व के शिक्षा - दर्शन में भी विशिष्ट स्थान रखता है।

शिक्षा की यह अभिकल्पना देने वाले महर्षि अरविंद महान योगी, क्रान्तिकारी, राष्ट्रवाद के अग्रदूत, प्रखर वक्ता एवं पत्रकार के रूप में जाने जाते हैं। महर्षि अरविंद उन पत्रकारों में से एक थे, जिन्होंने समाचार पत्रों के माध्यम से तत्कालीन जनमानस को स्वाधीनता संग्राम के लिए तैयार करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी।

श्री अरविंद का जन्म १५ अगस्त, १८७२ को कलकत्ता के एक बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता कृष्णधन घोष कलकत्ता के ख्यातिप्राप्त वकील थे, जो पूरी तरह से पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव में थे।

महर्षि अरविंद की शिक्षा-दीक्षा भी अंग्रेजी वातावरण में ही हुई थी। उनके पिता ने उन्हें पांच

वर्ष की अवस्था में दार्जिलिंग के लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल में दाखिल करवा दिया, जिसका प्रबंध यूरोपीय लोग करते थे। अरविंद अपने बाल्यकाल के सात वर्षों तक ही भारत में रहे, जिसके पश्चात उनके पिताजी ने उन्हें उनके भाइयों के साथ इंग्लैण्ड भेज दिया। जहां मैनचेस्टर के एक अंग्रेज परिवार में उनका पालन-पोषण हुआ।

महर्षि ने अपनी शिक्षा ब्रिटेन के सैंट पॉल स्कूल और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के किंग्स कॉलेज से प्राप्त की। पश्चिमी सभ्यता में पले-बढ़े महर्षि अरविंद एक दिन भारतीय संस्कृति के व्याख्याता होंगे, ऐसा शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। फरवरी १८९३ में महर्षि अरविंद भारत लौटे, ब्रिटेन से लौटने के पश्चात उन्होंने बड़ौदा कॉलेज में अध्यापन कार्य किया। यही वह समय था, जब बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप देश में १८५७ के पश्चात क्रांति की ज्वाला एक बार फिर से प्रखर हो रही थी। जिसका केन्द्र कलकत्ता ही था। महर्षि अरविंद बड़ौदा से कलकत्ता भी आते-जाते रहते थे। जहां वे क्रांतिकारी गतिविधियों में सहयोग करने लगे।

सन १९०७ में अरविन्द ने कांग्रेस के क्रांतिकारी संगठन नेशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन की अध्यक्षता की। इसी वर्ष अरविंद घोष ने विपिनचंद्र पाल के अंग्रेजी दैनिक वन्दे मातरम में काम करना शुरू कर दिया। महर्षि अरविंद का पत्रकारिता के क्षेत्र में इससे पूर्व ही पदार्पण हो चुका था।

उन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत सन १८९३ में मराठी साप्ताहिक "इन्दु प्रकाश" से की थी। जिसमें उनके नौ लेख प्रकाशित हुए थे, इनमें शुरूआती दो लेख उन्होंने "भारत और ब्रिटिश संसद" शीर्षक के साथ लिखे थे। इसके बाद १६ जुलाई से २७ अगस्त, १८९४ के दौरान उनकी सात लेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित हुई थी। वे लेख उन्होंने "वन्दे मातरम" के रचयिता एवं बांग्ला के महान साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी को श्रद्धांजलि देते हुए लिखे थे।

वन्दे मातरम में प्रकाशित उनके लेखों ने क्रांति के ज्वार में एक नया तूफान ला दिया। उनके लेखों के बारे में कहा जाता है कि भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में इतने प्रखर राष्ट्रवादी लेख कभी नहीं लिखे गए। अरविंद की पत्रकारिता की लोकप्रियता का ही कारण था कि कलकत्ता के लालबाजार की पुलिस अदालत के बाहर हजारों युवा एकत्र होकर वन्दे मातरम के नारे लगाते थे। जहां अरविंद के मामले की सुनवाई चल रही थी।

सितंबर १९०८ में वन्दे मातरम का प्रकाशन बंद हो गया। जिसके बाद उन्होंने १५ जून, १९०९ को कलकत्ता से ही अंग्रेजी साप्ताहिक कर्मयोगी और २३ अगस्त, १९०९ को बंगाली साप्ताहिक "धर्म" की शुरूआत की, जिनका मूल स्वर राष्ट्रवाद ही था। महर्षि अरविंद ने इन दोनों पत्रों में राष्ट्रवाद के अलावा सामाजिक समस्याओं पर भी लिखा। उनके इन पत्रों से विचलित होकर तत्कालीन वायसराय के सचिव ने लिखा था- "सारी क्रांतिकारी हलचल का दिल और दिमाग यही व्यक्ति है, जो ऊपर से कोई गैर कानूनी कार्य नहीं करता और किसी तरह कानून की पकड़ में नहीं आता।"

महर्षि अरविंद का लेखन उनके अंतिम समय तक अनवरत चलता रहा। सन १९१० में वे 'कर्मयोगी' और 'धर्म' को भगिनी निवेदिता को सौंप कर चन्द्रनगर चले गए। इसके बाद वे अन्तः प्रेरणा से पांडिचेरी पहुंचे। वहां भी उन्होंने "आर्य" अंग्रेजी मासिक की शुरूआत की, जिसमें उन्होंने प्रमुख रूप से धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों पर लिखा। "आर्य" मासिक में उनकी अगर रचनाएं प्रकाशित हुईं। जिनमें प्रमुख हैं लाइफ डिवाइन, सीक्रेट ऑफ योग एवं गीता पर उनके निबंध। महर्षि अरविंद का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय की पत्रकारिता में महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

पत्रकारिता में राष्ट्रवादी स्वर को स्थान देने वालों में अरविंद का नाम सदैव उल्लेखनीय रहेगा। ५ दिसंबर १९५० को महर्षि अरविंद देह त्याग कर अनंत में विलीन हो गए।

जेएनयू की बौद्धिक संस्कृति

शंकर शरण

जब एक संवाददाता ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) की चार दशक की उपलब्धियों के बारे में प्रश्न पूछा, तो वहाँ के रेक्टर का प्रमुख उत्तर था कि अब तक सिविल सर्विस में इतने छात्र वहाँ से चुने गए। दूसरी कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि वे गिना नहीं पाए जो समाचार में स्थान पा सकती।

सरसरी तौर से देखें तो कोई विशेष बात नहीं। विश्वविद्यालय के छात्र नौकरी की तैयारी करेंगे ही। पर जेएनयू मामले में एक असुविधाजनक प्रश्न उठता है। क्या सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए ही यह अति-विशिष्ट विश्वविद्यालय बना था, जिसे देश के संसाधन अति-उदारता से दिए जाते रहे हैं? उसके लिए तो वर्किंग वीमेन हॉस्टल की तर्ज पर 'नौकरी तैयारी हॉस्टल' बना देना ही पर्याप्त था, जहाँ शानदार आवास और बढ़िया भोजन मिलता हो! पैसे एक काम के लिए लिए जाएं, जबकि उससे काम दूसरा किया जाए ? क्या यह नैतिक है?

जो विश्वविद्यालय 'उच्च-स्तरीय शोध' के लिए बना था, जिस पर देश की जनता का अरबों रूपया नियमित खर्च किया जाता है? वह यदि केवल नौकरीकांक्षियों के लिए फर्स्ट-क्लास-फ्री-होटल जैसी चीज में बदल जाए, जहाँ रह कर वे नौकरी, व्यापार, राजनीति, देश-द्रोह समेत विविध धंधों से पैसा या प्रसिद्धि पाने का उपक्रम करें, यह निस्संदेह अनुचित है। ठीक है कि कानूनी दृष्टि से इसे घोटाला नहीं कहा जा सकता। परन्तु उचित और अनुचित का पैमाना केवल कानूनी भर नहीं होता।

कुछ लोग प्रश्न को इस रूप में रखने पर आपत्ति करेंगे। किन्तु जरा सोचें, यदि मँहगे रख-रखाव वाला कोई राष्ट्रीय खेल स्टेडियम केवल रैली या समारोह करने की सर्वोत्तम सुविधा के लिए ही प्रसिद्ध हो, तो क्या यह सार्वजनिक धन का उचित उपयोग कहा जाएगा? इसलिए, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय बनाने के लिए संसद में प्रस्तुत दस्तावेज से मिलाकर देखें कि विश्व-स्तरीय शोध संस्थान बनाने के नाम पर जनता के अरबों रूपयों का क्या उपयोग हुआ है। आरंभ से ही वामपंथी राजनीति के प्रचार का व्यवस्थित, सांगठिक तंत्र ही जेएयू की मुख्य पहचान रही है। इस शुरुआत का श्रेय वहाँ नियुक्त प्रथम प्रोफेसरों को ही है, जिनमें कुछ प्रमुख लोग कम्युनिस्ट पार्टी के थके हुए कार्यकर्ता थे। (राज थापर की आत्मकथा ऑल दीज इयर्स में उनकी जीवंत झलक मिल सकती है)। वस्तुतः उनकी नियुक्तियों से ही वह बौद्धिक गड़बड़ी शुरू हुई थी, जो कुटिल तकनीकों के सहारे एक स्थाई परंपरा बन गई है।

यह कोई संयोग नहीं कि आज तक देश को जेएनयू से किसी चर्चित शोध, अध्ययन, आविष्कार या लेखन संबंधी कोई समाचार सुनने को नहीं मिला। न केवल ज्ञान के किसी क्षेत्र में, बल्कि खेल-कूद, रंगमंच, कला या देश के नीति-निर्माण में भी वहाँ से कभी, कोई योगदान नहीं मिला। जबकि पश्चिमी देशों में प्रसिद्ध शोध विश्वविद्यालयों से सामाजिक, वैज्ञानिक, वैदेशिक संबंध आदि क्षेत्रों में ठोस योगदान मिलता है। इसीलिए वे प्रसिद्धि पाते हैं। किन्तु जेएनयू के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। यहाँ तक कि वहाँ से कोई जानी-मानी शोध-पत्रिका या सामान्य विद्वत् पत्रिका तक प्रकाशित नहीं हो सकी जिसे कोई अध्येता पढ़ना आवश्यक समझे।

यह दुखद स्थिति इसलिए है क्योंकि जहाँ

राजनीतिक लफ्फाजी का सर्वाधिकार हो वहाँ गंभीर अध्ययन, लेखन नहीं पनप सकता। इसीलिए केवल वामपंथी और भारत-विरोधी राजनीति के समाचारों से ही जेएयू की शोहरत होती है। पिछला नवीनतम समाचार भी यही आया था कि मोहाली के भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच के दौरान भारत के विरुद्ध नारे लगाए गए। बाद में भारत की जीत पर खुशी मनाने वालों पर हमला किया गया गया। उससे दो सप्ताह पहले ही वहाँ अशोक स्तंभ वाला राष्ट्रीय-चिन्ह जूते के नीचे मसले जाते पोस्टर प्रसारित किए गए। वहीं के मंच से अरुंधती राय ने भारत के विरुद्ध अपना नया विषवमन भी किया। जेएनयू से सदैव ऐसे ही समाचार आते हैं।

जैसे नक्सलियों द्वारा सत्तर सुरक्षा-बल जवानों की एकमुश्त हत्या किए जाने पर वहाँ जश्न मनाया गया। जेएनयू में हर तरह के, देशी-विदेशी, भारत-निंदकों को सम्मानपूर्वक मंच मिलता है। किन्तु देश के गृह मंत्री को बोलने नहीं दिया जाता। यहाँ तक कि उन के आगमन तक के विरुद्ध आंदोलन होता है! इसलिए, जेएनयू में भारत-विरोधी राजनीति अभिव्यक्ति स्वंतत्रता का मामला नहीं है। क्योंकि स्वतंत्र या देशभक्त स्वरों को वहाँ अधिकार नहीं दिए जाते!

यह कोई आज की बात नहीं। तीस वर्ष पहले भी जेएनयू में देश के प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दिया जाता था, जबकि लेनिन, स्तालिन, माओ और यासिर अराफात के लिए प्रोफेसर और छात्र संगठन मिलकर आहें भरते थे। वहाँ समाज विज्ञान और मानविकी के रिटायर्ड प्रोफेसरों के संस्मरण प्रमाण हैं कि 'जेएनयू कल्चर' के नाम पर वे 'स्तालिन सही थे या त्रात्सकी' पर रात भर चलने वाली बहसों के सिवा कुछ याद नहीं कर पाते। वहाँ से साल-दर-साल सिविल सर्विस के आकांक्षियों को मिलने वाली सुविधा और मूढ़ रेडिकलिज्म के फैशन से यह कड़वी सचाई छिपी रही कि विद्वत-उपलब्धि के नाम पर उन प्रोफेसरों के पास भी कहने के लिए कुछ नहीं है।

शोध का हाल यह है कि अधिकांश प्रोफेसर अपने शोधार्थियों के नकली या सतही काम को इसलिए तरह देते हैं कि वह सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं। यानी, कथित शोधार्थी जैसे-तैसे कुछ पन्ने बीच-बीच में लिख कर अपने प्रोफेसरों को देते हैं। जिसके आधार पर उन्हें 'संतोषजनक' कार्य का अंक मिलता है। उस निरर्थकता को प्रोफेसर जान-बूझकर नजर-अंदाज करते हैं ताकि कथित शोधार्थियों को साल-दर-साल हॉस्टल की सुविधा मिलती रहे! जैसे ही कोई नौकरी मिली, कई एम.फिल. या पीएच.डी छात्र अपने कथित शोध को वहीं छोड़ कर चलते बनते हैं। इस प्रकार, प्रति छात्र जो लाखों रूपये 'शोध अध्ययन' करने के नाम पर खर्च हुए, वह सीधे पानी में जाते हैं। जो कथित शोध पूरे भी होते हैं, वह भी केवल उसी विश्वविद्यालय की अलमारियों में जमा होने के सिवा कभी, किसी काम नहीं आते। कोई न उन्हें पढ़ता है, न खोजता है, क्योंकि सबको मालूम है कि उसमें कोई ऐसी चीज नहीं, जो पहले ही उपलब्ध न थी।

एसोसियेशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज की केंद्रीय पत्रिका 'यूनिवर्सिटी न्यूज' में प्रकाशित एक आकलन के अनुसार, हमारे विश्वविद्यालयों में सर्वोच्च शोध-डिग्री के लिए हो रहे काम की हालत यह है कि ८० प्रतिशत पीएच.डी. थीसिस 'नकली', 'कूड़ा' और 'दूसरों की नकल' होते हैं। अन्य विश्वविद्यालयों और जेएनयू में अंतर इतना भर है कि यहाँ वैसी ही एक कूड़ा थीसिस लिखने

के लिए जनता का चार गुना धन नष्ट होता है! कम से कम समाज विज्ञान और मानविकी में स्थिति यही है।

यदि शोध-छात्रों का हाल यह है, तो उन के अधिकांश प्रोफेसरों की हालत भी लगभग समानांतर है। कई महत्वाकांक्षी राजनीतिक सरगर्मियों में ही अधिक समय देते हैं। कुछ अन्य विद्वत् खानापूरी करते हैं। एक केंद्रीय शिक्षा संस्थान के निदेशक के अनुसार, जिन्हें यूजीसी और विविध उच्च-शोध संस्थानों द्वारा स्वीकृत किए जाने वाले शोध-प्रोजेक्टों की पर्याप्त जानकारी है, "अनेक प्रोफेसरों ने शोध के नाम पर एक ही चीज को बार-बार, और भिन्न-भिन्न संस्थाओं के आर्थिक सहयोग से करने की आदत बना ली है।" कहें कि जेएनयू के सबसे प्रसिद्ध इतिहास विभाग के प्रोफेसर ही इस के अच्छे उदाहरण हैं। उनके अलग-अलग संपूर्ण लेखन का सार-संक्षेप मात्र एक-एक पृष्ट में लिखा जा सकता है। क्योंकि उनमें शोध के बजाए राजनीतिक संदेश देने की केंद्रीयता और अधीरता रही है। सोवियत समाज विज्ञान पुस्तकों की तरह हर नई पुस्तक में एक ही पुरानी बात।

जेएनयू परिसर में मौजूद सारी पुस्तक दुकानें इसकी जीवंत प्रमाण हैं कि वहाँ केवल नौकरी की तैयारी या राजनीतिबाजी होती है। दुकानें लगभग संपूर्णतः विविध प्रतियोगिता परीक्षा संबंधी नोट, कुंजिका या फिर हर तरह के वामपंथी साहित्य से अटी रहती हैं। इतना ही नहीं, उन में इतिहास, राजनीति, साहित्य, दर्शन, अर्थशास्त्र आदि संबंधी प्रकाशन देखें तो लगेगा यह वर्ष २०११ नहीं, १९८० ई. है! आज भी जेएनयू की सभी दुकानों में वही रूसी, चीनी, यूरोपीय कम्युनिस्ट पुस्तक-पुस्तिकाएं, जीवनियाँ, पर्चे, आदि भरे हुए हैं जो तीस वर्ष पहले थे। वहाँ सजी ताजा हिन्दी पत्रिकाएं प्रायः केवल विभिन्न कम्युनिस्ट गुटों के प्रकाशन हैं, जिनमें दशकों पुराने मिथ्याचार, कुतर्क और इक्का-दुक्का समाचार मिलाकर 'विद्वत-विश्लेषण' किया जाता है। उनमें उन्हीं वामपंथी प्रोफेसरों की लफ्फाजियाँ हैं जिसमें दशकों से कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बीमारी की हद तक वही दुहराहट बार-बार छापी जाती है, जो बौद्धिक विष की तरह हर साल आने वाले नए छात्रों को छूता है। यही वामपंथी साहित्य 'अकादमिक' भी कहा जाता है! समाज विज्ञान और साहित्य के छात्र वही पुस्तकें, पत्रिकाएं पढ़ते या पढ़ने के लिए मजबूर किए जाते हैं। देश भर से प्रति वर्ष यहाँ आने वाले बेचारे भोले युवाओं के लिए चिंतन, मनन हेतु यही सीमित, बासी, भुखमरों सी खुराक है, जो जेएनयू की दुःखद पहचान बन गई है। जिनसे किसी पौष्टिकता की आशा कदापि नहीं की जा सकती। कोई चाहे भी तो समाज विज्ञान विषयों में नए चिंतन, शोध, आदि की प्रेरणा नहीं पा सकता। जेएनयू का वातावरण इसके नितांत विरुद्ध है।

इसीलिए यह विश्वविद्यालय 'उच्च-शोध' की आड़ में युवाओं के लिए मुख्यतः किसी नौकरी की खोज या राजनीति में कैरियर बनाने वालों का अड्डा भर बना रहा है। नौकरी की खोज यदि वहाँ का प्रमुख सेक्यूलर कार्य है, जिसे सब की सहानुभूति मिलती है, तो हिन्दू-विरोधी राजनीति वहाँ का प्रमुख मजहबी कार्य है जिसे वहाँ सक्रिय समर्थन है। वैचारिक, पारंपरिक, ढाँचागत समर्थन। हिन्दू-विरोधी, सरकार विरोधी, और प्रायः देश-विरोधी राजनीति का समर्थन। विडंबना यह कि यह सब करते रहने के लिए सारा धन उसी हिन्दू जनता, सरकार और देश से लिया जाता है!

इस प्रकार, सर्वाधिक संसाधन-युक्त इस केंद्रीय विश्व-विद्यालय का पूरा शोध-व्यापार एक दिखावटी काम में बदल कर रह गया है। यह भी एक स्कैम है। एक अपराध। जिस उद्देश्य से जेएनयू की स्थापना हुई थी, वह बहुत पहले कहीं छूट गया। बल्कि उस उद्देश्य से वहाँ कार्य का कभी आरंभ ही नहीं हुआ। यह विश्वविद्यालय केवल विविध रोजगार के लिए प्रयत्न करने और देश-द्रोही राजनीति सीखने-सिखाने के आरामदेह टिकाने के सिवा शायद ही कुछ रहा है। इसीलिए, जब भी जेएनयू की चर्चा होती है तो गलत कारणों से।

व्यंग्य

इस देश का यारों क्या कहना..

विजय कुमार

छात्र जीवन से ही मेरी आदत अति प्रातः आठ बजे उठने की है। पर आज सुबह जब कुछ शोर-शराबे के बीच मेरी आंख खुली, तो घड़ी में सात बज रहे थे। आंख मलते हुए मैंने देखा कि मोहल्ले में बड़ी भीड़ थी। कुछ पुलिस वाले भी वहां दिखाई दे रहे थे।

मोहल्ले की इस समस्या में शामिल होना मेरा भी कर्तव्य था। अतः ''रंज लीडर को बहुत है, मगर आराम के साथ..'' की तर्ज पर जल्दी से दो कप चाय पीकर कुछ जरूरी काम निबटाये और फिर शिवराज पाटिल की तरह ठीक से प्रेस किये हुए, कलफदार कपड़े पहनकर मैं बाहर आ गया। अब तक भीड़ और बढ़ गयी थी। कुछ पत्रकार और उनके चित्रकार साथी भी आंख मलते हुए वहां आ गये थे।

मैंने पूछताछ की, तो पता लगा कि शर्मा जी के घर चोरी हो गयी है। इस बारे में लोग तरह-तरह के अनुमान, संदेह और शंकाएं व्यक्त कर रहे थे, जिन्हें सुन-सुनकर शर्मा जी बौखला रहे थे।

स्थानीय पुलिस चौकी का मुखिया मोहल्ले वालों से पूछताछ कर जांच के नाम पर खानापूरी कर रहा था। तभी सायरन बजाती हुई नीली बत्ती वाली जीप के साथ बड़े दरोगा जी प्रकट हुए। शर्मा जी के साथ ही मोहल्ले वालों को भी अब कुछ आशा बंधी। दरोगा जी ने भी इधर-उधर देखा, कुछ सूंघने की सी कोशिश करते हुए उन्होंने शर्मा जी को एक ओर बुलाया। उनके कान में धीरे से फुसफुसाते हुए बोले - यह निश्चित रूप से किसी चोर का काम है।

शर्मा जी का मन हुआ कि दरोगा का मुंह नोच लें। जो बात सारे मोहल्ले को पता है, उसे दरोगा जी ऐसे बता रहे हैं, जैसे किसी गहरे कुएं से बड़ा भारी रहस्य खोज कर लाये हों।

कुछ-कुछ ऐसा ही पिछले दिनों मुंबई में हुए बम धमाकों के बाद हुआ। देश का बच्चा-बच्चा जानता है कि इनके पीछे उन्हीं पाकिस्तान प्रेरित इस्लामी आतंकवादियों का हाथ है, जो कई साल से भारत को अस्थिर करने के प्रयास में लगे हैं, पर देश के सत्ताधारी नेताओं के वक्तव्य देखें, तो ऐसा लगता है कि वे मूर्खों की काल्पनिक दुनिया में रह रहे हैं।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण जी ने फरमाया- इन हमलों से सिद्ध हो गया है कि आतंकी समूह अभी भी सक्रिय हैं और अपनी इच्छा से कहीं भी हमला करने में सक्षम हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने राज्य में गृहमंत्री की कुर्सी गठबंधन में शामिल दूसरे दल के नेता को देने को भी अपनी भूल माना।

तीन वर्ष पूर्व मुंबई में हुए आतंकी आक्रमण के कारण तत्कालीन गृहमंत्री को कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। अतः वर्तमान गृहमंत्री के लिए भी चौंच खोलना जरूरी था। वे दक्षिण मुंबई के सांसद और मंत्री बनने की खुशी मना रहे मिलिंद देवड़ा के साथ मुंबई पहुंचकर बोले - भारत के हर नगर को अब भी आतंकियों के समन्वित हमले से खतरा है। काश, कोई चिदम्बरम् का गला पकड़ कर पूछे कि फिर तुम

और तुम्हारी सरकार किस मर्ज की दवा है ?

देश में चाहे कैसी भी दुर्घटना हो जाए, मैडम इटली चुप ही रहती हैं, पर राहुल बाबा की चुप्पी उनके भावी जीवन के लिए उचित नहीं है। अतः वे बोले कि हर हमले को रोकना संभव नहीं है। उनका संदेश साफ था कि देशवासियों को आगे भी ऐसे हमलों के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए।

राहुल बाबा के बाद इस खानदान के भोंपू दिग्विजय सिंह न बोलें, ऐसा कैसे संभव है ? उन्होंने इन धमाकों का आरोप भी हिन्दू संस्थाओं पर लगा दिया। सुना है वे 'बम संदेश यात्रा' लेकर हिन्दू बस्तियों में जाने वाले हैं। वे लोगों को बताएंगे कि जब तक भारत में हिन्दू अल्पसंख्यक नहीं हो जाएगा, तब तक उसके वोट से बनी सरकार, उसकी जानमाल की क्षति के बावजूद, उसे ही आरोपी ठहराती रहेगी।

ऐसे शूरवीरों की भारत में कोई कमी नहीं है। कुछ लोग वक्तव्य देकर अपने कर्तव्य की इतिश्री मान लेते हैं, तो कुछ लोग मोमबत्तियां जलाकर या मौन जुलूस निकालकर। सच बोलने में सबकी जबान लड़खड़ाती है कि जब तक मजहबी तुष्टीकरण की इस विषबेल को जड़ ने नहीं काटेंगे, जब तक कसाब और मोहम्मद अफजल जैसे आतंकवादियों को सार्वजानिक रूप से फांसी नहीं देंगे, तब तक ऐसे हमले होते ही रहेंगे।

काम पर जाते समय मैंने देखा कि शर्मा जी के घर के बाहर भीड़ छंट चुकी है। दरोगा जी भी एक सिपाही को वहां छोड़कर हफ्ता वसूली के अपने नियमित काम पर चले गये थे। हां, शर्मा जी अब भी सिर पर हाथ रखे अपने भाग्य को कोसते हुए वहां बैठे थे। कुछ दूरी पर हो रहे किसी कार्यक्रम में एक गाना जोर से बज रहा था –

ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का मस्तानों का। इस देश का यारो क्या कहना...।

यह गाना मैंने हजारों बार सुना है। आज भी इसमें इतना दम है कि बच्चों से लेकर बूढ़ों तक को सड़क पर, तथा अनशनरत नेताओं को राजघाट पर थिरकने को मजबूर कर देता है, पर मुझे लगा कि वर्तमान परिस्थिति में इसमें निम्न संशोधन कर देना चाहिए।

वक्तव्य वीर नेताओं का, नाकारा और बेहयाओं का। इस देश का यारों क्या कहना..।

(लेखक : 'राष्ट्रधर्म' मासिक के पूर्व सहायक सम्पादक हैं)

प्रिय मित्रों,

शिक्षा क्षेत्र की प्रतिनिधि पत्रिका के रूप में 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' का अगस्त अंक आपके समक्ष प्रस्तुत है। इसमें विभिन्न समसमायिक घटनाक्रमों तथा भ्रष्टाचार से संबंधित कई महत्वपूर्ण आलेखों एवं खबरों का संकलन किया गया है। आशा है यह अंक आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप उपादेय साबित होगा।

'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' से संबंधित अपने सुझाव और विचार हमें नीचे दिये गये संपादकीय कार्यालय के पते अथवा ई-मेल पर अवश्य भेजें-

"छात्रशक्ति भवन"
690, भूतल, गली नं. 21
फैज रोड, करोल बाग,
नई दिल्ली-110005.
फोन : 011-43098248
ई-मेल : chhatrashakti.abvp@gmail.com
वेबसाइट : www.abvp.org
ब्लॉग : chhatrashaktiabvp.blogspot.com

खेती लाभ का धंधा बना
खुशहाल किसान बना

शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

प्रदेश के किसानों के हितों की पूरी सुरक्षा हो रही है अब

- किसानों को 1 प्रतिशत ब्याज पर कम अवधि का ऋण देने वाला पहला राज्य।
- गेहूं पर 100 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने वाला देश का पहला राज्य।
- इस साल 46 लाख मीट्रिक टन से अधिक का गेहूं उपार्जन।
- सहकारी बैंकों ने जारी किये 98 लाख से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड।

अन्नदाता किसान का पूरा सम्मान - **मध्यप्रदेश**

ABVP

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिष

Akhil Bharatiya Vidyarthi Parisha